वाहन उद्योग में आत्मनिर्भरता को बढ़ाएं : मोदी

वाहन निर्माण में भारत को बनाना है वैश्विक केंद्र, मिलकर करें काम

तीन करोड़ वाहनों की बिक्री से उद्योग को मिली रफ्तार

नयी दिल्ली, 11 सितंबर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को आत्मनिर्भर भारत का प्रमुख स्तंभ बताते हुए कहा है कि अब वक्त आ गया है जब सरकार और उद्योग को एकजुट होकर वाहन निर्माण की पूरी वैल्यू चेन में आत्मनिर्भरता हासिल करनी होगी.

मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे इस क्षेत्र में भारत को वैश्विक हब बनाने की दिशा में कदम तेज करने होंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वाहन उद्योग को आत्मनिर्भर भारत मिशन की रीढ़ बताते हुए कहा कि इस क्षेत्र में संपूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए उद्योग और सरकार को मिलकर काम करना होगा.

उन्होंने यह संदेश घरेलू वाहन निर्माता कंपनियों के संगठन सियाम के वार्षिक अधिवेशन के उद्घाटन सत्र के दौरान भेजा, जिसे टाटा मोटर्स के एमडी शैलेश चंद्रा ने पढ़ा. मोदी ने कहा, वाहन उद्योग ने न केवल अर्थव्यवस्था को रफ्तार दी है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता और मोबिलिटी में भी बदलाव लाया है.

आज यह मेक इन इंडिया का अगुवा बन गया है और भारत को एक उभरता हुआ वाहन निर्माण केंद्र बना दिया है. प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत भविष्य की ट्रांसपोर्ट प्रणाली की ओर तेजी से बढ़ रहा है. हरित ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ते इस क्षेत्र में स्टार्टअप्स की भूमिका को उन्होंने महत्वपूर्ण बताया, खासकर ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में.

> इस अवसर पर केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी ने भी वीडियो संदेश के माध्यम से कहा कि देश में हर साल तीन करोड़ से अधिक वाहनों की बिक्री हो रही है, जो उद्योग की तेज़ प्रगति को दर्शाता है. उन्होंने यह भी कहा कि कुछ विशेष कलपुर्जों के निर्माण के लिए आवश्यक स्टील का उत्पादन अब भारत में ही किया जाएगा. सियाम अध्यक्ष श्री चंद्रा ने कहा कि यह उद्योग अब 20 लाख करोड़ रुपये के राजस्व के साथ जीडीपी में 15 प्रतिशत योगदान देता है. इसमें 3 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार भी मिला है

टीवी नरेंद्रन ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए

नई दिल्ली 11 सितंबर. टाटा स्टील लिमिटेड के मुख्य अधिशासी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं. यह जानकारी संगठन की विज्ञप्ति में दी गई है.

नरेंद्रन ने इस पद पर अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेज लिमिटेड की प्रबंध निदेशिका सुनीता रेड्डी का स्थान लिया है जिनका एक साल का कार्यकाल पूरा हो गया . एमआईएमए, भारत में कॉर्पोरेट प्रबंधकों का एक प्रतिष्ठित निकाय है. इसकी स्थापना 1957 में हुई थी और पूरे देश में 68 शहरों और क्षेत्र में इसके सहायक संगठन कार्यरत हैं. यह विदेशी संगठनों के साथ मिलकर भी काम करता है.

अदानी को 800 मेगावाट का ठेका मिला

5 .838 रु. यूनिट की दर पर ठेका मॉडल पर बनेगा संयंत्र

1600 मेगावाट क्षमता के निर्माण का ठेका प्राप्त हुआ

खुली निविदा में 800 मेगा वॉट क्षमता का ठेका अभी कुछ दिन पहले ही मिला था. निविदा प्रक्रिया हाल ही में संपन्न हुई है.

अहमदाबाद, 11 सितंबर (वार्ता). अदानी पावर लिमिटेड (एपीएल) को निविदा प्रक्रिया के तहत मध्य प्रदेश में एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा अनूपपुर जिले में प्रस्तावित वृहद बिजली परियोजना की 800 मेगावाट क्षमता की एक और इकाई का ठेका मिला है.

एपीएल ने गुरुवार को बताया कि उसे ग्रीन शू विकल्प के तहत प्राप्त इस अनुबंध के साथ इस परियोजना में कंपनी के पास कुल 1600 मेगावाट क्षमता के निर्माण का ठेका प्राप्त हुआ है. इसे वहां

अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल ताप विद्युत संयंत्र से बिजली की आपूति

मध्य प्रदेश में 800 मेगावाट की यह अतिरिक्त क्षमता का अनुबंध है. पहले ठेके पर दी गई 800 मेगावाट क्षमता पर लागू 5 .838 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की समान दर पर आवंटित किया गया है. इस तरह एपीएल मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में डिज़ाइन, निर्माण, वित्त, स्वामित्व और संचालन (डीबीएफओओ) मॉडल के तहत स्थापित की जाने वाली एक नई 1600 मेगावाट (800-800 मेगावाट की दो इकाई वाली) अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल ताप विद्युत संयंत्र से बिजली की आपूर्ति करेगी.

भारतीय वाहन उद्योग में नंबर वन बनने की क्षमता

जापान को पछाड़ तीसरे स्थान पर अब लक्ष्य शीर्ष स्थान : गडकरी

इथेनॉल से बढ़ेगी आय घटेगा प्रदूषण

नयी दिल्ली, 11 सितंबर (वार्ता). सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि भारतीय वाहन उद्योग का देश की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है और इसमें दुनिया में पहले नंबर पर पहुंचने की क्षमता है.

गडकरी ने यहां घरेलू वाहन निर्माता कंपनियों के संगठन सियाम के वार्षिक अधिवेशन में कहा कि कुछ साल पहले भारतीय वाहन उद्योग दुनिया में सातवें स्थान पर था, आज हम जापान को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गये हैं. उन्होंने कहा, मेरा विश्वास है आप सब लोगों की क्षमता पर. आप सब लोग यदि मिलकर काम करेंगे तो हम वाहन सेक्टर में दुनिया में नंबर एक पर जा सकते हैं. पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का प्रधानमंत्री का जो सपना है उसमें इस उद्योग की भूमिका सबसे अहम है.

एक संवाद सत्र में उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण में 40 प्रतिशत वाहनों के कारण होता है. सरकार अब प्रदूषण कम करने के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा दे रही है. इसके अलावा बीएस सात मानक लाने पर विचार किया जा रहा है. उन्होंने उद्योग से कहा कि सरकार कुछ अलग नहीं करेगी, यह भी यूरोपीय मानक के अनुरूप ही होगा. पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण के बारे में गडकरी ने कहा कि ई20 (20 प्रतिशत मिश्रण) से आगे कोई कदम उठाते समय वाहन उद्योग से भी चर्चा की जायेगी.

उन्होंने सोशल मीडिया पर ई20 के खिलाफ पिछले दिनों चलाये गये अभियान को पेड बताते हुये कहा कि कहने को तो यह अभियान इथेनॉल के खिलाफ था लेकिन राजनीतिक रूप से यह उन्हें निशाना बनाने के लिए था. उन्होंने कहा कि इथेनॉल पेट्रोलियम आयात का विकल्प है, इससे प्रदूषण कम होता है और किसानों की आमदनी बढ़ाने वाला है.

> उन्होंने कहा कि वह पुराने वाहन को स्क्रैप करके नये वाहन खरीदने वालों के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में छूट पर भी सरकार के अंदर पैरवी कर रहे हैं. देश में हर साल 60 लाख टन स्क्रैप स्टील का आयात किया जाता है जबकि नयी स्क्रैप नीति लाने के बाद अब 3.76 लाख टन स्क्रैप स्टील की घरेलू आपूर्ति हो रही है.

स्पाइसजेट को 5 करोड़ डॉलर के शेयर निवेश

8 .95 करोड़ डॉलर का सौदा, रखरखाव के लिए 7 .96 करोड

नयी दिल्ली, 11 सितंबर (वार्ता). किफायती विमान सेवा कंपनी स्पाइसजेट ने कार्लाइल एविएशन पार्टनर्स के साथ 8.95 करोड़ डॉलर का एक समझौता किया है, जिसके तहत भविष्य के विमानों और इंजनों के रखरखाव के लिए 7.96 करोड़ डॉलर की नकद रखरखाव निधि और अपने पट्टे संबंधी देनदारी के भुगतान के लिए 99 लाख डॉलर की नकद रखरखाव क्रेडिट राशि प्राप्त हुई है.

यह समझौता एयरलाइन की नकदी में उल्लेखनीय वृद्धि करता है और इसके चल रहे पुनर्गठन प्रयासों को समर्थन प्रदान करता है. ये तरलता वृद्धि कार्लाइल एविएशन पार्टनर्स और उसकी संबद्ध संस्थाओं के साथ समग्र निपटान समझौते का हिस्सा हैं, जिसके तहत पट्टाकर्ता कुल 12.118 करोड़ डॉलर के कुछ पट्टा दायित्वों का पुनर्गठन करेंगे. साथ ही कुल पांच करोड़ डॉलर के इक्विटी शेयर जारी करेंगे.

निपटान समझौते में एक ऐसी व्यवस्था भी प्रदान की गई है जिसके तहत, यदि पट्टाकर्ता जारी किए गए शेयरों की बिक्री से पांच करोड़ डॉलर से अधिक की आय प्राप्त करते हैं, तो इस अतिरिक्त राशि का एक हिस्सा भविष्य के पट्टा दायित्वों की पूर्ति के लिए लगाया जाएगा. प्रमोटर के पास वैधानिक लॉक-इन अवधि और दोनों पक्षों के बीच अनुबंधित किसी भी अतिरिक्त लॉक-इन अवधि की समाप्ति पर पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर ऐसे इक्विटी शेयर खरीदने का विकल्प/अवसर होगा.

सेबी बोर्ड की बैठक शुक्रवार को, आईपीओ नियमों में ढील संभव

नई दिल्ली, 11 सितंबर. की नई योजनाएँ भारत के बड़ी कंपनियों के प्रक्रिया को सुगम बनाने की दिशा में एक बड़े बदलाव का संकेत हैं. प्रस्ताव के अनुसार, जिन कंपनियों की बाजार पूंजीकरण 50,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ के बीच है, उनके लिए न्यूनतम सार्वजनिक प्रस्ताव को 1,000 करोड़ निर्धारित करने का सुझाव है. इसके साथ ही, पोस्ट-इशू पूंजी का कम से कम 8त्न हिस्सेदारी सार्वजनिक दर्शकों के लिए होगी. न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता की तालिका भी ढीली की जाएगी वर्तमान में तीन वर्षों के भीतर 25त्न हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी होती है, प्रस्तावित नियमों के अन्तर्गत इसे पाँच वर्षों में पूरा करना होगा.

बाजार में टिकाऊ बढ़त के लिए क्रोमा की नई रणनीति

नई दिल्ली 11 सितंबर. वित्त वर्ष 2024-25 में टाटा ग्रुप की कंपनी इनफिनिटी रिटेल लिमिटेड, जो क्रोमा ब्रांड का संचालन करती है, ने अपने रिटेल बिजनेस को मजबूती देने के लिए 1,000 करोड़ का नया निवेश प्राप्त किया है. यह निवेश टाटा डिजिटल द्वारा किया गया है, जिससे कंपनी की अधिकृत पूंजी अब 6,000 करोड़ हो गई है.

हालांकि कंपनी का घाटा पिछले साल के 986 करोड़ से बढ़कर इस साल 1,091 करोड़ हो गया है, लेकिन सकारात्मक बात यह रही कि कंपनी की आमदनी 6.7त्न बढ़कर 19,228 करोड़ पहुंच गई है. कंपनी के अनुसार, यह वर्ष उनके लिए बदलाव का साल रहा. क्रोमा ने अपने ऑपरेशन मॉडल में रणनीति अपनाई है. इसका उद्देश्य तेज, कुशल और लाभदायक संचालन है. इस रणनीति के तहत कंपनी ने मार्केटिंग और सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में लागत कम की है, जिससे मुनाफे के मार्जिन में सुधार हुआ है. ऑनलाइन बिक्री भले ही 36त्न घट गई हो, लेकिन इसका कारण रणनीति में बदलाव है. क्रोमा अब केवल उसी बिक्री पर ध्यान दे रही है जो टिकाऊ और लाभदायक हो.

शेयर बाजारों में तेजी जारी

मुंबई, 11 सितंबर (वार्ता). विदेशों से मिले मिश्रित संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में गुरुवार को तेजी रही और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी-50 सूचकांक तीन सप्ताह बाद 25 हजार अंक के पार बंद हुआ.

बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 123.58 अंक (0.15 प्रतिशत) चढ़कर 81,548.73 पर पहुंच गया जो 25 अगस्त के बाद का इसका उच्चतम स्तर है. निफ्टी-50 सूचकांक में 32.40 अंक यानि 0.13 प्रतिशत की तेजी रही और कारोबार की समाप्ति पर 25,005.50 अंक पर रहा.

दिवाली से पहले पीएफ निकालना होगा आसान

नई दिल्ली, 11 सितंबर. दिवाली से पहले प्रोविडेंट फंड (पीएफ) खाताधारकों के लिए राहत भरी खबर आ सकती है. केंद्र सरकार पैसा और से निकालने की सुविधा देने जा रही है. इससे करोड़ों ईपिएफओ सब्सक्राइबर्स को सीधे निकासी और खर्च करने की आज़ादी मिलेगी. साथ ही केंद्र सरकार दिवाली से पहले ईपिएफओ सब्सक्राइबर्स के लिए एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है. श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में 10-11 अक्टूबर को ईपिएफओ की बोर्ड बैठक होगी, जिसमें दो बड़े प्रस्तावों पर चर्चा होगी. एटीएम से पीएफ पैसा निकालने की सुविधा न्यूनतम पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 1,500-2,500 तक करने का प्रस्ताव सरकार का उद्देश्य लगभग 8 करोड़ सदस्यों को डिजिटल माध्यम से अधिक सुविधा देना है.

होंडा की बाइक्स खरीदना होगा सस्ता सौदा

ग्राहक को सीधे मिलेगा लाभ एक्स-शोरूम कीमत में कमी

नई दिल्ली, 11 सितंबर. अगर आप होंडा की बाइक या स्कूटर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह सबसे सही समय हो सकता है. दरों में कटौती के बाद होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने गुरुवार को ऐलान किया कि वह पूरी राहत का फायदा ग्राहकों को देगी.

इसका सीधा असर कीमतों पर पड़ेगा और 350सीसी तक की बाइक्स अब 18,800 तक सस्ती हो जाएंगी. होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने 11 सितंबर को घोषणा की कि कंपनी अपने तक के स्कूटर और मोटरसाइकिलों की कीमतों में 18,800 तक की कमी करेगी. यह कटौती केंद्र सरकार द्वारा दर को 28प्रतिशत से घटाकर 18प्रतिशत किए जाने के निर्णय के बाद की गई है. कंपनी ने अपने बयान में कहा कि वह त्रस्ञ्ज परिषद द्वारा लिए गए फैसले का सीधा लाभ ग्राहकों को देगी. होंडा के उत्पाद पोर्टफोलियो में आने वाले सभी 350सीसी तक के वाहन अब कम कीमत में उपलब्ध होंगे. निदेशक योगेश माथुर ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा, दोपहिया वाहनों और स्पेयर पार्ट्स पर GST में कटौती एक समयोचित और दूरदर्शी कदम है. इससे गाड़ियाँ ज्यादा किफायती बनेंगी और वाहन उद्योग को गति मिलेगी.

भाजपा का प्रत्याशियों के लिए मापदंड

हर सीट पर 11 से 13 दावेदारों के नाम पर विचार

पटना. बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारी तेज कर दी है. महागठबंधन और एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर खींचातानी जारी है. सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन और एनडीए गठबंधन में मथापच्ची जारी है. इसी बीच बीजेपी ने सीट बंटवारे को लेकर नई रणनीति तैयार की है. बीजेपी भाजपा प्रत्याशियों का चयन कैसे करेगी इसको लेकर एक मूल मंत्र तैयार किया गया है. इसके तहत टिकट उसी प्रत्याशी को मिलेगा जिसकी जीतने की संभावनाएं अधिक होगी.

सूत्रों की मानें तो भाजपा ने इस बार 2020 की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है. बताया जा रहा है कि भाजपा एक सीट के लिए 3 उम्मीदवारों का चयन करेगी. जिनमे से एक को टिकट मिलेगा. जानकारी अनुसार बीजेपी करीब 1300 संभावित प्रत्याशियों की स्कैनिंग करेगी. हर सीट पर 11 से 13 दावेदारों के नाम पर विचार होगा. उनमें से 3 नामों की फाइल दिल्ली भेजी जाएगी और अंतिम फैसला पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा.

पहले प्रत्याशियों की लोकप्रियता का आकलन किया जाएगा कि क्षेत्रीय स्तर पर प्रत्याशियों की पहचान कितनी है. जिसके बाद फीडबैक संग्रह किया जाएगा जो वोटरों, समाजसेवियों और संगठन से राय से होगा. स्थानीय नेतृत्व की सहमति ली जाएगी. विधानसभा प्रभारी और जिलाध्यक्ष की राय से उम्मीदवारों का चयन होगा. प्रदेश स्तर पर समीक्षा की जाएगी. जिसके बाद संभावित नामों की सूची दिल्ली भेजा जाएगा. सर्वे रिपोर्ट तैयार किया जाएगा जिसमें पिछले चुनावों के आंकड़े और जीत-हार का अंतर होगा. 5 साल का आकलन किया जाएगा काम, लोकप्रियता और वरिष्ठ नेताओं की राय पर प्रत्याशियों का चयन होगा. कास्ट फैक्टर और जीतने की संभावना पर जोर दिया जाएगा. प्रदेश स्तर से जो नाम दिल्ली भेजे जाएंगे, उनमें यह स्पष्ट करना होगा कि प्रत्याशी को टिकट क्यों मिलना चाहिए. साथ ही संबंधित विधानसभा की जातिगत समीकरण और सामाजिक संरचना की रिपोर्ट भी भेजी जाएगी.

> **बूथ से प्रखंड तक सक्रियता**
>
> भाजपा का शीर्ष नेतृत्व बूथ और प्रखंड स्तर पर कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय कर चुका है. बूथ स्तर पर कार्यकर्ता घर-घर जाकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं. पेंशन बढ़ोतरी, रोजगार, 125 यूनिट फ्री बिजली, आयुष्मान कार्ड और किसान निधि जैसी योजनाओं का प्रचार किया जा रहा है. प्रखंड स्तर पर समाजसेवियों, मुखियाओं और स्थानीय प्रभावशाली लोगों से संपर्क साधा जा रहा है. नुक्कड़ सभाओं और बाजार बैठकों के जरिए चुनावी माहौल बनाने की कोशिश हो रही है.

सिटिंग सीट पर भी राजद में होड़

नीतीश कुमार की जदयू में शांति

मधेपुरा. समाजवाद की राजनीति का केंद्र रहे मधेपुरा जिले का सूबे की राजनीति में हमेशा दखल रहा है. समाजवाद के पुरोधा कहे जाने वाले भूपेंद्र नारायण मंडल व वंचितों को मुख्यधारा से जुड़ने का अधिकार देने वाली मंडल कमीशन के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल का भी गृह क्षेत्र है.

यह शरद यादव व लालू यादव की भी कर्मभूमि रही है. दोनों नेता एक-दूसरे को पराजित कर संसद पहुंचे और केंद्र सरकार में मंत्री भी बने. पूर्णिया के वर्तमान सांसद पप्पू यादव की राजनीतिक यात्रा भी 1990 में मधेपुरा से ही शुरू हुई थी. वे सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव जीतने में सफल रहे थे. इसके बाद पप्पू दो बार मधेपुरा के सांसद रहे. जनसंघ को मधेपुरा में पहली जीत दिलाने वाले राजनंदन यादव हों या फिर विद्याकर कवि, वीरेंद्र सिंह सरीखे राजनेताओं की भी यह कर्मभूमि रही है. बाद के दिनों में मधेपुरा जिले की राजनीति शरद, नीतीश और लालू के इर्दगिर्द ही घूमती नजर आई. यही वजह है कि हर चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक पखवाड़े का पड़ाव मधेपुरा में रहता है.

जदयू की सिटिंग सीट पर किसी और नाम की चर्चा भी नहीं

इसी तरह, सिंहेश्वर (सुरक्षित) सीट से विधायक चंद्रहास चौपाल के साथ-साथ पूर्व विधायक अमित भारती, डॉ. कुंदन कुमार सुमन, मुखिया वीरेंद्र शर्मा समेत कई अन्य नेता भी खुद को रेस में बता रहे हैं. ठीक इसके उलट जदयू की सिटिंग सीट पर किसी और नाम की चर्चा भी नहीं है. आलमनगर से विधानसभा उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव और बिहारीगंज से निरंजन मेहता ही संभावित प्रत्याशी होंगे.

मणिपुर में क्या बनेगी नई सरकार?

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर की यात्रा पर जाने वाले हैं. उसके बाद राज्य की राजनीति में बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है. कहा जा रहा है कि मणिपुर में नई सरकार का गठन हो सकता है.

ध्यान रहे राज्य में छह महीने से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है और विधानसभा निलंबित रखी गई है. राष्ट्रपति शासन लगा कर विधानसभा को अनंतकाल तक निलंबित नहीं रखा जा सकता है. राज्य में विधानसभा चुनाव में अभी डेढ़ साल का समय है तो इतने समय तक विधानसभा निलंबित नहीं रखी जाएगी. अगर सरकार नहीं बनती है तो विधानसभा भंग करनी होगी.

यह भी कहा जा रहा है कि दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक उप राज्यपाल का फैसला भी मणिपुर के कारण अटका है. वहां राज्यपाल बना कर भेजे गए पूर्व केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को वहां से वापस आना है. वह नहीं सरकार बनने के बाद ही संभव हो पाएगा. भाजपा की राजनीतिक समस्या यह है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को किनारे करके नई सरकार का गठन करना चाहता है.

विशेष | **कांग्रेस ने शुरू की लॉबिंग, ठाकरे को किया दरकिनार**

एमवीए में एलओपी के लिए मचेगा घमासान!

मुंबई. महाराष्ट्र विधान परिषद में शिवसेना (यूबीटी) विधायक अंबादास दानवे का नेता विपक्ष के रूप में कार्यकाल खत्म होने के बाद अब इस पद के लिए कांग्रेस नेताओं ने अपनी लॉबिंग तेज कर दी है. इसके तहत कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार, वरिष्ठ नेता बालासाहेब थोरात और सीनियर विधायक अमीन पटेल ने मातोश्री में शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ चर्चा की.

विजय वडेट्टीवार ने कहा कि हमने उद्धव ठाकरे के साथ विधान परिषद में विपक्ष के नेता पद पर चर्चा की है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के अध्यक्ष शरद पवार के मुंबई आने के बाद हम उनसे भी चर्चा करेंगे. बता दें कि विधान परिषद में नेता विपक्ष के रूप में दानवे का कार्यकाल 29 अगस्त को समाप्त हो गया था. उद्धव से मिलने के बाद कांग्रेसी नेताओं ने विधान परिषद के सभापति राम शिंदे से भी मुलाकात की. सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस नागपुर में 8 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र से पहले इस पद को फाइनल करना चाहती है.

राज ठाकरे से पल्ला झाड़ा- वडेट्टीवार ने साफ तौर से कहा कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच गठबंधन को लेकर आपस में क्या चर्चा हुई, उससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने कहा कि आगामी नगर निगम चुनावों में मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे को महाविकास आघाड़ी में साथ लेना है या नहीं, यह फैसला दिल्ली में हमारे आलाकमान के स्तर पर लिया जाएगा. अभी हम लोग इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं.

सतेज पाटिल पर चर्चा- वर्तमान में विधान परिषद में शिवसेना ठाकरे गुट के 6 और कांग्रेस के 8 सदस्य हैं. एसीपी शरद पवार गुट के 2 सदस्य हैं. उद्धव ठाकरे स्वयं भी विधान परिषद के सदस्य हैं. संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस विधान परिषद में विपक्ष के नेता का पद चाहती है. सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की ओर से सतेज बंटी पाटिल के नाम पर चर्चा चल रही है. फिलहाल वे विधान परिषद में कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं.

> **विपक्ष के लिए पर्याप्त विधायक नहीं**
>
> 2024 में हुए विस चुनाव में शिवसेना यूबीटी ने 20 सीटें जीतीं तो वहीं कांग्रेस ने 16 और राकां (शरदचंद्र पवार) ने 10 सीटें जीतीं. समाजवादी पार्टी 2 और सीपीआई (एम) की-1 सीट को मिलाने से विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी के 49 विधायक होते हैं. 288 विधायकों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में विरोधी पक्ष नेता के लिए 10 फीसदी सीट के फार्मूले के हिसाब से किसी भी विपक्षी दल के पास पर्याप्त संख्याबल यानी अपने अकेले के 29 विधायक नहीं हैं.